Striking power of the IAF

*352. SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA:
SHRI P. PRABHAKAR REDDY:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the striking power of the Indian Air Force is fast declining, as reported in the Times of India, dated the 14th November, 1998;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the urgent steps taken or proposed to be taken to retrieve the situation?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

Post of CMD in Eastern Coalfields Ltd.

*354. SHRI JIBON ROY:
SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) since when the post of Chairman and Managing Director in Eastern Coalfields Limited (ECL) has been lying vacant;

(b) the reasons for the delay in finding a permanent CMD inspite of the sickness of the company; and

(c) the likely date by which a permanent CMD would be posted?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI DILIP RAY): (a) The post of CMD, ECL is lying vacant since 30.11.97.

(b) The present acting CMD has filed a Writ Petition in the Delhi High Court seeking his regular appointment as CMD. The High Court vide its order dated 28.1.98 has granted a stay. Hence the post of CMD, ECL could not be filled up on regular basis as the matter is sub-judice.

(c) Filling up the post on regular basis can be taken up on the vacation of the stay or final disposal of the Writ Petition.

Fuel Shortage in Assam

*355. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether there is any fuel shortage in the State of Assam;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to supply LPG to rural areas of Assam?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI K. RAMAMURTHY): (a) and (b) There was a marginal back-log in LPG supplies in the State of Assam during April, 98 to Oct., 98 due to heavy rains in the State, causing floods and disruption of road traffic and occasional bandhs in the State during the period.

(c) IOC has been conducting regular survey of markets including the rural markets to explore the feasibility of putting up LPG Distributorships in rural areas also. 20 locations in Assam in Rural Areas have been approved under LPG Marketing Plan 96—98 for opening new LPG distributorships.

Irregularities in ITDC

*356. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether officials and ex-officials of I.T.D.C. have cheated Government to the tune of lakhs of rupees during the past one year,

(b) if so, the facts and details thereof;

(c) the steps teken by Government to recover the amount from the officials involved; and

(d) the steps taken to provide foolproof system so that the officers may not indulge in such unfair means in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI OMAK APANG): (a) No such cases of cheating ITDC to the tune of lacs of rupees by its employees during the last one year ending November, 1998 has come to light/notice of the management.

(b) to (d) Do not arise.

तेल पूल लेखे में घाटा

*357. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1989-90 से तेल पूल लेखाओं में निरन्तर घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका वर्ष-वार अद्यतन ब्यौरा क्या है और घाटे की प्रतिशतता कितनी-कितनी रही है;

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस घाटे को पूरा करने के लिए अब तक पेट्रोलियम उत्पादों में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि की गई है; और

(ङ) इस समय देश के तेल पूल घाटे की अद्यतन स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री के० राममूर्ति): (क) और (ख) तेल कंपनियों की संचयी बकाया राशियों की वर्षवार स्थिति संलग्न विवरण-क में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

(ग) तेल पूल खाते में घाटे को नियंत्रित करने की दृष्टि से, सरकार ने सितम्बर, 1997 में यह निर्णय लिया था कि तेल कंपनियों के प्रति तेल समन्वय समिति की देयताओं के आंशिक भाग को सरकार द्वारा विशेष सरकारी बांड जारी करके तेल कम्पनियों को एक मुश्त भुगतान करते हुए निपटा दिया जाएगा। साथ साथ तेल कंपनियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले विशेष सरकारी बांडों के रूप में सरकार से प्राप्त होने वाली इस राशि का वे निवेश करें।

कम्पनियां (अहस्तांतरणीय) विषेश सरकारी बांड 2005" जिसकी कुल राशि 12,984 करोड़ रुपए बनती है

उपर्युक्त व्यापक पैकेज के तहत "10.5 प्रतिशत तेल सरकार ने 02.03.98 से तेल कंपनियों के लिए जारी किए थे।

"आर" ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने यह निर्णय भी लिया था कि एक चरणबद्ध ढंग से सुधार शुरू करते हुए प्रशासित मूल्य व्यवस्था को समाप्त किया जाए। विशेषज्ञ तकनीकी ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर टर्मिनल वर्ष अर्थात 2001-02 तक प्रशासित मूल्य व्यवस्था के कार्यक्रम को चरणों में समाप्त करने के ब्यौरे तथा शुल्क संरचना पर सरकार ने नवम्बर, 1997 में पुनः निर्णय लिया।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-ख में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ङ) विशेष सरकारी बांड जारी कर दिए जाने के बाद 03.03.98 से 30.11.98 तक तेल कंपनियों को कुल 6804 करोड़ रुपए का "लेखागत" भुगतान किया गया है और 30.11.1998 तक 6180 करोड़ रुपए शेष रह गए है।

विवरण—क

तेल कंपनियों की संचयी बकाया राशियों की वर्ष-वार स्थिति

वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर तेल कंपनियों की संचयी बकाया राशियां	
	रु०/करोड़	प्रतिशत अंतर
1989-90	1,798	
1990-91	2,908	61.73
1991-92	5,095	75.21
1992-93	4,904	(–) 3.75
1993-94	5,050	2.98
1994-95	3,765	(–) 25.45
1995-96	5,701	51.42
1996-97	15,976	180.23
30.6.97	18,271	14.37